होगी, गरीब उस कार को खरीदकर पेट्रोल के रूप में अपना खून जलाएगा, यह एक सच्चाई है जिसे स्वीकार करना पड़ेगा, पर ट्रैक्टर पर वे एक्साइज़ घटाने का काम करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। इसके साथ-साथ जो कृषि यंत्र हैं, उनको भी एक्साइज ड्यूटी से मुक्त करने का काम करें। महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं। मान्यवर, मैंने पहले भी इस सम्मानित सदन में कहा है कि ट्रैक्टर कम्पनियां आज किसान का जितना शोषण कर रही हैं, दोहन कर रही हैं कि आज तक इस मुल्क में किसी को यह पता नहीं है कि कौन सा ट्रैक्टर कितनी कीमत का है। मैंने पहले भी इस सदन में उदाहरण देकर बताया था कि पंजाब में ट्रैक्टर बनाने के लिए नई-नई कम्पनियां आई हैं। उन्होंने किसी कम्पनी से पिछला हिस्सा ले लिया, किसी से गेयर बॉक्स ले लिया, किसी से बॉडी ले ली और किसी से इंजन लेकर वे सब पार्ट्स को मिलाकर ट्रैक्टर तैयार करती हैं। वे स्वयं ट्रैक्टर की कोई एक कील तक नहीं बनाती हैं। वे बाहर से ही उसको असेम्बल कराकर, बेच देते हैं। मैंने छोटा थ्रेशर बनाने वाली एक कम्पनी 'सोनालीका' का जिक्र किया था। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसका पता लगाएं कि यह कम्पनी ट्रैक्टर बनाकर, आज कहां पहुंच गई है? इस कम्पनी की और कोई मैन्युफेक्चरिंग नहीं है। सारा विभाग आंख बंद करके बैठा है, एक ट्रैक्टर की कीमत में, पचास हजार से एक लाख तक का अंतर डीलर टू डीलर है। इसमें किसान लुट रहा है और किसान को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने किसान के लिए रेट आफ इन्टरेस्ट घटाने का काम किया है। उन्होंने बजट में इसका प्रावधान भी किया है कि आप सात परसेंट पर किसान को ऋण देंगे। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, परन्तु आपने इसकी एक सीमा भी लगा दी है। आपका जो एग्रीक्लचर इम्पलीमेंट है, उसमें अगर ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्यूबवैल की कीमत लगाएं और यदि किसान लेना चाहे तो उसकी कीमत 6-7 लाख बैठती है। आपने इसकी सीमा तीन लाख तक की लगा दी है, लेकिन कृषि मंत्री जी का बयान तो दो लाख का ही आया था। मेरा यह अनुरोध है कि जब किसान बैंक से ऋण लेता है तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। जो उसका प्रोजेक्ट है, उसको 5 परसेंट, 6 परसेंट के रेट आफ इन्टरेस्ट पर जाना चाहिए। आप किसान पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हर रोज अखबारों में ऐड निकलती है, जिसके तहत आदमी कार खरीदता है, वह गैर जिम्मेदार होता है और वह कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी नहीं देता है। उसको उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सात परसेंट ब्याज पर पैसा मिलता है। अगर किसान को भी सात परसेंट पर ब्याज दे दिया है तो उसको सीमाओं में मत बांधिए। हां, यह जरूर है कि जो हमारे मल्टिनेशनल बैंक्स हैं, वे मलाई खा रहे हैं। यदि सरकार ने इन मल्टिनेशनल बैंकों पर अंकुश नहीं लगाया तो आपके नेशनलाइज्ड बैंक रुग्ण होते चले जाएंगे। जो हमारे प्रॉयरटीज के क्षेत्र हैं, उनको एडवांस करने के लिए सरकार को बात करनी चाहिए। मान्यवर, जो आर.बी.आई. की गाइड लाइंस है, उनके अनुसार किसान का ब्याज का पैसा जो कैलकुलेट होगा तो वह साल में एक बार होगा। इस बात को भारत सरकार भी कहती है और वित्त मंत्रालय भी कहता है। सारे बैंक्स त्रैमासिक गणना करते हैं और वे किसान से ज्यादा ब्याज वसूल रहे हैं, इसको रोका जाना चाहिए, यही मेरा अनुरोध है। मान्यवर, मैंने बजट देखा है और मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने सिंचाई पर जो धन की व्यवस्था की है क्या वह पर्याप्त है? आज भी हमारी कितनी भूमि असिंचित है। मेरा यह अनुरोध है कि अगर वर्तमान में और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना अवश्य कर लें कि जो हमारा पम्प सैट है, चाहे वह दस हार्स पावर की मोटर का हो या 15 हार्सपावर की मोटर का हो, जो हमारा पम्प है, उसको 100 परसेंट छूट देनी चाहिए, ऐसा

मेरा अनुरोध है। अगर सिंचाई होगी तो फसल भी अच्छी होगी। दूसरी बात भूमि की आती है। लैंड डेवलपमेंट के लिए आज ऊसर भूमि भी है, ऊंची-नीची भूमि भी है। उनको विकास करने के लिए बैंकों को निर्देश दें कि प्रॉयोरिटी पर, कम ब्याज पर उसको ऋण दें। माननीय मंत्री जी को ऐसे निर्देश देने होंगे और ऐसी व्यवस्था करनी होगी। दूसरी बात यह है कि जो घटिया खाद और बीज का मजाक हो रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए कृषि मंत्री जी को सोचना होगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं। मान्यवर, आज भी किसान को अपनी फसल लगाने के लिए कोई जगह नहीं है और बजट में इस बात का पर्याप्त प्रावधान नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान के खेत के नजदीक कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाऊसेज बनाए जाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, वह सफेद हाथी बना हुआ है। जो आपका CWC सैंटर वेयर हाऊसकॉरपोरेशन है, आप इनको निर्देश दें कि ये गांवों में जाएं। ये CWC के लोग शहर में ही कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाऊस क्यों बनते हैं और क्यों नेशनल हॉर्टिक्लचर बोर्ड शहर में कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए लोन नहीं देता है? वे गांव में और बागवानी के पास जाकर, गांवों के लोगों को ऋण दें ताकि वे अपने कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाऊस बना सकें।

मान्यवर, मैं आयकर के बारे में भी कहना चाहूंगा कि आयकर में चोरी रोकी जाए। इसके लिए मेरा माननीय मंत्री ज़ी से अनुरोध है कि इसकी सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख की जानी चाहिए, इसलिए यह आयकर में छूट देने का मामला है। मान्यवर, रामदेव का किस्सा आया है और मैंने कल ही अखबार में पढ़ा है कि बापू आसाराम ने पचास लाख रुपए दान में दिए हैं। आप आयकर के दायरे के नाम पर ऐसी संस्थाओं को 80-G या कोई जो अन्य धारा है, उसमें छूट दे देते हैं। आप रोज भाषण देने के नाम पर एक-एक आदमी से चार-हजार, पांच हजार रु0 निकालते हो और औद्योगिक घराने इन्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर आप हरिद्वार जाएं, तो देखकर नहीं लगता कि यह साधु-संन्यासी का मामला है। मैं हरिद्वार से 80 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूं। हम सूफी, साधु और संतों को अच्छी तरह से जानते हैं। ये लोग साधु, सूफी और संतों की जमात में नहीं आते। साधु-संत कोई पैसे की मोहब्बत नहीं किया करते हैं। जिन लोगों का अरबों-खरबों का खेल है, उन लोगों को 80(जी) के तहत छूट नहीं देनी चाहिए, उसे समाप्त करना चाहिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि बड़े औद्योगिक घराने इनसे जुड़े हुए हैं, इनको sponsor करते हैं और अपना नंबर दो का पैसा नंबर एक और नंबर एक का पैसा नंबर दो में करने का काम करते हैं।

मान्यवर, वृंदा जी बोलीं, उनके बोलने के बाद इतना दबाव बना दिया कि आज अगर माननीय मंत्री जी सीधे नहीं चाहेंगे, तो किसी अधिकारी की हैसियत नहीं है कि वह इन बड़ी शक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सके। एक षड्यंत्र के तहत ऐसा हो रहा है। आप एक लाख रुपए वाले को पकड़कर जेल में भेज रहे हैं और जो लोग बड़ा काम कर रहे हैं, उनकी तरफ आप देख नहीं रहे हैं।

मान्यवर, एक हास्यास्पद घोषणा हुई। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, आपने पेयजल पर एक्साइज ड्यूटी की छूट दे दी, अच्छा होता कि आप दुग्ध-उत्पादक को सब्सिडी देते, उसको interest free loan देते। अगर ऐसा हो जाए, तो इस देश में दूध की नदियां बहेंगी। आप AIDS की बात करते हैं, आप कैंसर की बात करते हैं, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर तामसिक भोजन खाओगे, तो निश्चित रूप से दिमाग खराब होगा और इससे AIDS भी फैलेगा,

कैंसर भी फैलेगा, लेकिन अगर आप सात्विक रहेंगे, तो इन सब बीमारियों से दूर रहेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि दुग्धपालकों को सब्सिडी देनी चाहिए और उनको interest free loan देना चाहिए।

मान्यवर, हमारे यहां मुजफ्फरनगर में स्टील इंडस्ट्री है। मुझे कभी-कभी उन लोगों से बैठकर बात करने का मौका मिला। पूरे हिंदुस्तान का बजट यहां बनता है। आपको यह जानकर दु:खद आश्चर्य होगा कि आज इधर की सारी इंडस्ट्री ठप्प हो रही है। झारखंड और उड़ीसा में बिना एक्साइज़ pay किए हुए, रोज रैक के रैक रॉ-मैटीरियल उतर रहा है। वहां बिजली की चोरी होगी, एक्साइज़ की चोरी होगी और अधिकारी बैठकर देखते रहेंगे।

महोदय, एक बार एक आदमी मेरे पास आया। उसने मुझे बताया कि मेरे साले के पास 5 करोड़ रुपए नंबर दो के हैं। माननीय राज्य मंत्री जी चले गए हैं, मैंने इसी सम्मानित सदन में कहा है, मैंने इनके दफ्तर में जाकर कहा है, कोई उसको पूछने तक नहीं गया। उस आदमी ने बताया कि फलां जगह रखे हुए हैं, फलां मकान में, फलां कमरे में रखे हुए हैं। यह सब मेरे साथ जाकर राज्य मंत्री जी को बताया, लेकिन उसको कोई पूछने तक नहीं गया। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को इन मामलों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

मान्यवर, हमारे यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुगर मिल्स जो बिजली उत्पादन कर रही हैं, उस बिजली की ऐसी चोरी करती हैं कि बिजली उत्पादन को, उसी premises में दूसरी इंडस्ट्री लगाकर, किराए पर देकर बिजली बेचने का काम करती हैं, बहुत नुकसान करती हैं और आखिर में राजस्व का नुकसान केन्द्र सरकार को भुगतना पड़ता है।

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से एक अनुरोध है कि अभी जो राज्य overdraft ले रहे हैं, जिन राज्यों की अर्थ-व्यवस्था खराब है और वे overdraft ले रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। वे किसानों की जमीन कम पैसे में acquire करेंगे और उसको बड़े औद्योगिक घरानों को एक रुपया गज में दे देंगे। ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसी मुल्क में हुई हैं। आखिर इसकी क्या आवश्यकता है? केन्द्र सरकार को ऐसी सरकारों पर अंकुश लगाना होगा। क्यों आप गरीब किसानों की जमीन acquire करके बड़े औद्योगिक घरानों को एक रुपया गज में देते हैं? अगर औद्योगिक घराना कोई उद्योग लगाता है, तो व्यापार करने के लिए लगाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए लगाता है, लाभ कमाने के लिए लगाता है, वह किसी को खैरात बांटने के लिए उद्योग नहीं लगाता है।

महोदय, आज मैंने एक अखबार में पढ़ा कि 10-15 दिन पहले किसी स्टेट में बड़ी छूट की घोषणाएं की गई थीं कि जो उनके यहां शुगर इंडस्ट्री लगाएगा, उसको यह छूट मिलेगी, वह छूट मिलेगी। औद्योगिक घरानों से adjustments होंगे, छूट दे दी जाएगी, लेकिन जब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ना जल रहा था, जब वहां का किसान आत्महत्या कर रहा था, तब उसे कोई अनुदान और छूट देने के लिए नहीं आया था। सरकारें ऐसी होनी चाहिए - Government for the People, Government by the People, Government of the People होनी चाहिए, लेकिन आज Government of the Industrialists हो रही है, इसको रोकने का काम मंत्री जी को करना होगा, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

मान्यवर, कुछ हमारे कारपोरेशंस हैं। आपने dis-investment की योजना चलाई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे हर स्टेट में Road Transport Corporation है, बसें भी हैं, सवारियां भी हैं, स्टाफ भी है, चलाने वाले भी हैं, अगर कहीं कोई बीमार है और आप उन्हें अनुदान दे रहे हैं, तो किसलिए दे रहे हैं? आप उसे बंद करके निजी क्षेत्र में दे दीजिए, यह मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है।

मान्यवर, उत्तरांचल में एक विशेष मज़ाक हुआ। उत्तरांचल को, हिमाचल के साथ-साथ केन्द्र सरकार की ओर से विशेष पैकेज दिया गया। आप यह जानकर ताज्जुब करेंगे कि उसमें यह हुआ कि अगर इस खेत में इंडस्ट्री लगाएगा तो छूट मिलेगी, बराबर के खेत में लगाएगा तो छूट नहीं मिलेगी। इस दायरे में पूरे प्रदेश को लें। यह रकबा तय कर दिया गया कि इस गाटा संख्या में होगा, तो छूट का भागीदार होगा और इस गाटा संख्या में नहीं होगा, तो नहीं होगा। मेरा अनुरोध है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा और निश्चित रूप से वे दूसरा काम करेंगे। मेरा ऐसा अनुरोध है कि इसमें छूट पूरे प्रदेश में एक सी होनी चाहिए।

मान्यवर, आपने सहकारी बैंकों, सहकारी सोसायटियों पर कर लगाने की बात कही है। निश्चित रूप से यह पीड़ादायक है। छोटा किसान को-ऑपरेटिव से लोन लेता है। किसी भी एक बड़े उद्योगपति ने आज तक को-ऑपरेटिव बैंक से लोन नहीं लिया। सहकारिता में भ्रष्टाचार है, हम इसे स्वीकार करते हैं। उसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाइए, नीति बनाइए, उनकी ऑडिट कराइए, परन्तु इस पर टैक्स लगा कर छोटे किसान की कमर मत तोड़िए। आज भी 70 प्रतिशत किसान दो-तीन रुपया सैकड़ा महीने पर यानी कि 24-36 परसेंट तक ब्याज पर साहूकार से पैसा लेता है। किसान इसलिए आत्महत्या करता है, क्योंकि वह बर्बादी की कगार पर है।

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार को संवेदनशील होना चाहिए ...**(समय की घंटी)**... मान्यवर, अभी तो पाँच ही मिनट हुए हैं।

श्री उपसभापति : 12 मिनट हो गए हैं।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक : मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ।

मान्यवर, सरकार को इसमें संवेदनशील होना पड़ेगा। अन्यथा आज हमारे ग्रामों में आधारभूत सुविधा नहीं है। आधारभूत सुविधा न होने के कारण शहरों पर दबाव बढ़ रहा है। शहरों पर दबाव बढ़ने से दिक्कतें शहरों पर भी होंगी। मान्यवर, आपने लघु उद्योगों की सूची से कुछ और उद्योगों को निकाल दिया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अगर आप आदमी को रोजी देंगे, तो वह काबिल बनेगा और रोटी देंगे, तो वह बेकार बनेगा। रोटी खाकर मुफ्त का रोटीखोर कभी तरक्की नहीं कर पाया। सब्सिडी आदमी को बेकार बनाती है, अनुदान उसे बेकार बनाता है।

आज आप जो छात्रवृत्ति देने का काम कर रहे हैं, इसे जाति के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर देने पर विचार करें, चाहे आप उसी जाति में करें, तो अच्छा लगेगा। युवा कल्याण पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिस देश के युवा सबल होंगे, जिस देश के युवा अच्छे होंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, निश्चित रूप से वह देश उन्नति करेगा।

मान्यवर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वास्तव में एक बधाई के योग्य योजना है। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। मेरा अनुरोध है कि कम-से-कम मंडल स्तर पर या पहले स्टेट स्तर पर जो एम्स की शाखाएँ खोलने का प्रस्ताव आया था, उसको क्रियान्वित करना चाहिए। आज नजला, जुकाम, बुखार से आदमी नहीं मर रहा है, बल्कि कैंसर जैसी बीमारी, चेस्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी से आदमी मर रहा है। उनके हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, कितने शहरों में हैं, सरकार को इसे देखना होगा।

मान्यवर, निश्चित रूप से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए सभी बधाई देंगे। यह एक प्रशंसनीय योजना है। गाँव के लोगों को सरकार से आशा की एक किरण जगी है। परन्तु केवल दो सौ जिलों का चयन हुआ है। उसका क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। पूरे राष्ट्र में इसे लागू करना होगा, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

मान्यवर, बुनकर, दस्तकार चाहे अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक, वे बुरे हाल से गुजर रहे हैं। बिचौलिए उनका शोषण करते हैं। उनका माल बाजार में नहीं बिक पा रहा है। जब से आपने इम्पोर्ट खोला है, वे बेचारे कहीं स्टैण्ड नहीं कर पा रहे हैं। बिचौलिए उसी सामान को, जो अच्छा सामान वे बनाते हैं, लेकर एक्सपोर्ट कर देते हैं और उस बेचारे को कुछ नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में सरकार का दायित्व बनता है कि उनकी ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : हरेन्द्र साहब, आप समाप्त कीजिए।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक : सर, मैं एक मांग तो कर लूँ।

श्री उपसभापति : ठीक है, आप एक मांग कर लीजिए।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक : आप उसे मनवा दें, तो अच्छा रहेगा।

मान्यवर, मेरी मांग यही है कि ट्रैक्टर, पम्पसेट और किसान के कृषि यंत्रों को एक्साइज से मुक्त किया जाए। आपने मेरठ तक जो एक्सप्रेस हाइवे बनाने की बात की है, इसे बढ़ा कर रुड़की तक कर दिया जाए। मेरठ तो दिल्ली से मात्र 60-70 किलोमीटर है। अगर आप आगरा तक बना सकते हैं, चंडीगढ़ तक बना सकते है, अगर रुड़की तक बना देंगे, तो निश्चित रूप से उत्तरांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो सबसे उपेक्षित प्रदेश है, उसको फायदा होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि माननीय मंत्री जी मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। मान्यवर, मैंने जिन लोगों का नाम लिया है, जो किसान को लूट कर, मैं विशेषकर ट्रैक्टर कंपनियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ऐसे नए-नए ट्रैक्टर आ जाते हैं, कभी पुलसर आ जाता है, कभी हैरिसन आ जाता है, कभी अंगद आ जाता है, कभी सोनालिका आ जाता है, कहीं प्रीत आता है, कहीं स्टैण्डर्ड आता है, कोई हंस आता है, कोई कंस आता है, इनको आप निश्चित रूप से देख लें कि इन लोगों ने किसान को लूट कर कितना पैसा इकट्ठा किया है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI R. P. GOENKA (Rajasthan): Mr. Deputy Chairman, Sir, I stand here to support the Budget proposals. It is a growth-oriented Budget and as the Finance Minister said, 'it is a path of honour and courage'.

However, I have been listening to some of the speeches made this afternoon, particularly, of Mr. Yashwant Sinha. I have great respect for him. But, today, I was very disappointed. He did not see anything good in the Budget. So, if he approaches all the proposals with a negative mind how can he see positive things? He mentioned about coal. He said it is an indirect privatisation. Does he know? He must be knowing it. But, he decided to ignore that coalmines would be given to captive conjunction, to the people like power units or cement units. It is not privatisation. If a person gets coalmines and he mines additional coal, he cannot sell it in the market. He has to sell it to the consumer. Sir, he also ignored the five-mega projects which have been announced and it is an open bid. Anyone can make a bid and the most competitive bidder would get those power projects. Power is the essence of growth. I heard Kalraj Mishraji also. He mentioned about *Sarva Shiksha Abhiyan*. He talked about students there. I will quote a figure from the Finance Minister's Speech. Ninety-three percent of children in the age group of six to fourteen years are in school and the number of children not in school has come down to less than a crore. Sir, our esteemed colleagues, Members whom I respect, either don't do their homework or they tend to forget to do their homework. Now, I will come and tell you why we have to celebrate this Budget. I will give you few instances from the Budget Speech. "The growth is 8.1 per cent compared to 7.5 per cent previously..." Growth in domestic savings has increased to 29.1 per cent and capital formation has increased to 30.1 per cent. Mr. Yashwant Sinha mentioned that how the foundation of this growth was laid during the NDA's time. No one is questioning. No one is questioning that during the NDA time certain good measures were taken. But, this does not meant that the present growth is incapable of taking India to a higher level. The GDP growth this year is recorded at 8.1 per cent. And, if this trend continues, we shall reach 10 per cent at the end of the Tenth Plan. One of the speakers said that this growth rate of 8.1 per cent is second only to China. Sir, China, I think, has a growth rate of 9 per cent. We are second. Yes. But, 8 per cent growth is a very good growth rate. It gives us courage. It makes us work hard. This Budget, we can say in one word, is rural growth-oriented Budget. May I give some figures?

The National Rural Employment Guarantee Scheme was launched. We hope to spend about Rs. 12,000 crores on this. Who says there was no proposal before this Government came to power? But the massive scale in which we are taking up different projects was not there.

Sir, under the Rajiv Gandhi Grameen Vidudikaran Yojana 34,000 MW would be added and 41,000 non-electrified villages would get electricity. You may say why only 41,000 villages? It should be 51,000 villages. It should be 61,000 villages. But, we are reaching 41,000 villages with electrification. A lot of harsh words were used on Bharat Nirman programme. It is a laudable programme. It is a bottom of a pyramid. Unless we give jobs to people in rural areas, how would a country grow? It cannot grow. Our hon. Prime Minister said that the Bharat Nirman programme is going to be one of the growth stories of the world in the coming decade. That is the difference between a successful man and not so successful man. If you can see the future, guess the future and act according to it, then you become successful.

Sir, the Budget on Health and Family Welfare has been increased by 22 per cent. You will again say what happened to the setting up of six AIIMS-like hospitals. But the total growth is 22 per cent. We are ignoring the fact. On education, the Budget is 13 per cent higher. It takes us to Rs. 24,000 crores. And, by spending this money, we are not achieving all we wanted to achieve. But 93 per cent of the children will be in schools. You may say that it is not 100 per cent. Yes, it is not 100 per cent. But we are going towards that. It is 93 per cent.

The Mid-Day Meal Scheme was criticized. We have gone up to certain standards. Some people say that why not we go to higher standards also. Yes, we will go. But we can't jump all the storeys in one go. So, we are going step by step.

Some people mentioned about drinking water. In this Budget, 56,000 habitations and 1,40,000 schools would be covered. It is satisfactory that total rural credit will be Rs. 1,75,000 crores. Some people don't appreciate because the numbers are too big. I have read, it is not mentioned in this House, that all this is being done because State elections are coming. In a federal country, like India, almost every year we will have a few States going for elections. So, that means that Budget should keep a blind eye!

Another criticism, in this House and outside, was that the inflation is skyrocketing. 4 per cent inflation is skyrocketing! In Hindi, there is a word *'mandbuddhi'*. I am *mandbuddhi*. So, in my *budhi*, '4 per cent' does not look skyrocketing. I will read out a paragraph from the Prime Minister's speech, what it said about this Budget. It says that all these schemes,

mentioned in the Budget, would cover every village in India having a population of one thousand or more would have water supply; every village would have a telephone; every village would be electrified. Is this is not for *aam aadmi*? Sir, it is not proper for me to pose a question to you, but does *aam aadmi* live only in cities. India's *aam aadmi* lives in rural areas. And, this is an ambitious Budget. Here, we need cooperation of the Central and the State Governments and the people, at large. If we cooperate, with each other we will be successful. This is, if my words are unparliamentary, you may remove it, a * good Budget. Thank you, Sir.

श्री सूर्यकान्तभाई आचार्य (गुजरात): माननीय उपसभापति महोदय, I am very much obliged ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: क्या आप दस मिनट लेंगे?

श्री सूर्यकान्तभाई आचार्य: आप जितना भी समय देंगे।

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा): सर यह इनका मेडन स्पीच है।

श्री उपसभापति: अच्छा मेडन स्पीच है।

श्री सूर्यकान्तभाई आचार्य: महोदय, यह बजट बहुत ही निराशाजनक है। अगर इस बजट पर हम आम आदमी की प्रतिक्रिया लेंगे तो पता चलेगा कि उन्हें भी यह निराशाजनक ही लगा है। हम भारत को प्रभुसत्ता सम्पन्न बनाने की दिशा में पदार्पण कर रहे हैं और भारत को प्रभुसत्ता सम्पन्न बनाने के स्वप्न साकार करने के लिए इनका यह बजट और इनकी नीतियां सक्षम नहीं हैं। भारत को प्रभुसत्ता सम्पन्न बनाने के कार्य में वर्तमान सरकार असफल रही है, they have missed the time.

दसवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का उनका लक्ष्य 8% था, लेकिन जब आर्थिक सर्वे करवाया गया तो इसे केवल 7% बताया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक नियोजन और गतिशीलता का अभाव सा रहा है। आज वृद्धि दर की बात करना एक दिवा स्वप्न की भांति प्रतीत होता है। इतना ही नहीं मध्यम वर्ग पर इतना अधिक बोझ डाल दिया गया है कि उनकी कमर ही टूट जायेगी।

आज हमारा देश विश्व प्रतिस्पर्द्धा में खड़ा हुआ है और उसका बेइस इन्फ्रास्ट्रक्चर। इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी हम इस बजट से निराश हुए हैं।

मैं बिजली क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं, अप्रैल-दिसम्बर 2005 में बिजली की वृद्धि दर 4.7% थी। और आज 2006 में इसी समय यह दर 6.5 परसेंट है। माथा के सुविधा के साथ इनका सीधा संबंध है उनमें भी मेरी आशा फलीभूत नहीं हुई है। यह बजट किसानों के लिए मजाक मात्र है। दस देश का किसान देवा के कारण आत्म-हत्या कर रहे हैं। एन0डी0ए0

---

* Not recorded.

सरकार ने उनके आखिरी दिनों में सात टका ब्याज की जहरात की थी। अब यू0पी0ए0 सरकार ने यह उनकी अपनी योजना है, ऐसा बता करके उसका गुणगान कर रहे हैं। अर्थ यह है कि इस बाबत दो वर्ष में यू0पी0ए0 सरकार ने उनके अमलीकरण के बारे में कुछ भी नहीं किया है। नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन -उसमें गांधी जी की जन्म भूमि पोरबन्दर को ही बकात रखा है। गुजरात की जो केपिटल -गांधीनगर है उनको बकात रखा है। उनका इसमें समास किया होता तो अच्छा होता। जहरात तो बजट में ऐसी हुई कि बीस हजार जितनी वाटर बॉडी ग्राम विस्था में बनाएंगे। 6 लाख देहातों में। उनकी वाटर बॉडी सरेरास 30 गांवों के अंदर एक वाटर बॉडी है, तो यह मजाक नहीं तो क्या है। इसी तरह आवासों के बारे में भी है। आठ लाख तिरेसठ हजार ग्रामीण आवास बनाने की योजना जाहिर की है। एक गांव में पूरे दो आवास भी, इससे तो हो नहीं सकता है। अपने मंत्री जी की मेंटेलिटी ऐसी लगती है कि इम्पॉर्टेड डिंक्स -पेप्सी, कोका कोला को सस्ता करना चाहते हैं और मारूति कार भी सस्ती करना चाहते हैं। मगर कॉमन मैन के लिए जो चीजें उपयोग में आ रही हैं वे सस्ती हों, ऐसा उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है। महोदय, बजट का उपयोग क्या कोई डिफेंस के बारे में हो सकता है, इसमें नहीं है। बजट इम्प्रेस करता है खुला ऑफर। उन पर वह लाइन नहीं ली है। दुख की बात यह है कि किसानों के बारे में अपने हाउस में दो-तीन बार चर्चा हुई। कैसी चर्चा हुई वह हम सब जानते हैं। तो किसानों के बारे में, आज जो किसानो की स्थिति है, आज उनको जो अपगात करने जा रहे हैं। तो इस बाबत पर सोचना चाहिए, यह तो पं0 जवाहर लाल नेहरू की देन है। फर्स्ट टू प्लान है। वह एग्रीकल्चर के आधार नहीं बने हैं, इण्डस्ट्री के आधार पर बने हैं और इण्डस्ट्री भी हैवी इण्डस्ट्री। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं कि मेरे जैसा मध्यम वर्ग का आदमी जिसके पास तीन-चार लाख रुपया है और उनके आधार पर व्यापार करना चाहते हैं।वह कार का व्यापार करेंगे, तो एक कार आयेगी। उसको रखने के लिए गैराज चाहिए। उसके ऊपर गैराज का भाड़ा पड़ेगा, तो उसका दिवाला निकल जायेगा। अगर वह कोई छोटा उद्योग करे, कोई छोटा ट्रेड करे, थोड़ा-थोड़ा नफा लेकर के, कहते हैं कि फोरमेशन करे, तो पहला और दूसरा प्लान था, उसमें कैपिटल फारमेशन का स्टेप था, वह हमने नहीं लिया । आज हम देख रहे हैं कि देश की हालत कैसी है।

उपसभापति महोदय, देश में कई सैक्टर हैं - पब्लिक सैक्टर है, प्राईवेट सैक्टर है और ऐसा ही एक कोआपरेटिव सैक्टर है। कोआपरेटिव सैक्टर पर गुजरात के अलावा किसी दूसरे स्टेट ने इतना ध्यान नहीं दिया है। कोआपरेटिव सैक्टर कोई नफे के लिए नहीं है, वह प्रोफिट के लिए नहीं है, वह जो व्यापार करते हैं, व्यवहार करते हैं वह देहातों के, किसानों के हित के लिए करते हैं। अगर उसमें फायदा होता है तो वह किसी को इंडिव्युजली फायदा नहीं होता है, उसमें जैसे कैपिटलिस्टों को नफा होता है, वैसे नफा नहीं होता है। It is one kind of a service to the farmer. अभी तक कोआपरेटिव सैक्टर पर टैक्स नहीं था, मंत्री जी ने उनके प्रोफिट के ऊपर टैक्स डालकर इस सैक्टर को खत्म करने की कोशिश की है। देहात में कोआपरेटिव सैक्टर के बाद बैंक्स आते हैं, जिन्हें वे ग्रहण करते हैं। उन पर भी इसका असर होने वाला है। Sir, the cooperative sector is the guarantee of democracy. If we don't want capitalism in our country, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इसका अल्टरनेटिव क्या है? इसके दो-तीन अल्टरनेटिव हैं, उनमें से एक अल्टरनेटिव सहकारी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रहपूर्वक कहूंगा कि कोआपरेटिव सैक्टर के नफे के ऊपर जो टैक्स लगाया है, वह टैक्स हटा लेना चाहिए।

7.00 P.M

एक दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने देश के पास इतना बड़ा, लम्बा समुद्र का किनारा है, उसका उपयोग करने के लिए मंत्री जी ने कुछ सोचा ही नहीं है। मैं गुजरात से आता हूं, गुजरात में बड़ा लम्बा समुद्र का किनारा है, समुद्र को रत्नागर कहते हैं और समुद्र में से कई चीजें हो सकती हैं, मैं दो चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। I was the Deputy Chairman of the Planning Commission in the state of Gujarat. इनके बारे में थोड़ा मैंने सोचा था। अर्थशास्त्रियों का असैसमेंट और विज़न ऐसा है कि आगामी 20 साल में गुजरात में सौराष्ट्र प्रदेश की जो आबादी है, जो पापुलेशन है, उस पापुलेशन की 50 परसेंट पापुलेशन सागर के किनारे पर रहती है। कितना बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि गुजरात ट्रेडर्स का देश है, तो ट्रेड में हम किसी को आगे नहीं जाने देंगे। सारे सागर के किनारे पर ट्रेड पनपेगा और उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। इतना ही नहीं, भारत का जो मध्य भाग है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये सब अपना माल मुम्बई से भेजते हैं। तब जितना खर्चा आता है, उससे बहुत कम खर्च अगर सौराष्ट्र से एक्सपोर्ट के लिए भेजेंगे, तब आएगा। जब इंटरनेशनल ट्रेड हो गया है, जब सारा विश्व एक ग्राम बन रहा है, तब यह अनिवार्य है कि कोस्टल डेवलपमेंट के बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए। It is in the national interest.

श्री उपसभापति : सात बज गए हैं। आपकी मेडन स्पीच है, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता।

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश): मेडन स्पीच है। वे दो-तीन मिनट में खत्म कर देंगे।

श्री सूर्यकान्तभाई आचार्य : महोदय, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज किसानों की जो हालत है, उसमें क्या कोई नयी दिशा हम ले सकते हैं? Agriculture should be the base of the progress of India. India is an agricultural country. कैपिटल की जो व्याख्या आजकल Western economies करते हैं, वह सत्य नहीं है। Capital goods produce करने वाली इंडस्ट्री कैपिटल नहीं हो सकती। जमीन कैपिटल है, खेती कैपिटल है क्योंकि उसमें से कोई नयी चीज़ उत्पन्न होती है, नया कैपिटल उत्पन्न होता है। इसी तरह से जंगल भी कैपिटल है, पहाड़ है, वह भी कैपिटल है, जो आबादी है, वह भी देश की कैपिटल है। सच्ची कैपिटल जो है, वह हिन्दुस्तान के पास इतनी अधिक है कि दुनिया की सब ताकतों के सामने वह टिक सकता है। एग्रीकल्चर के बारे में सोचना चाहिए कि small farms को भी economic holding में कैसे परिवर्तित करना है। Economic holding पांच-दस एकड़ की होती है। मुझे यह डर है कि जो capitalism की ओर हमारे देश को ले जाया करते हैं, उनके कारण आने वाले दिनों में ऐसी फार्मिंग आ सकती है कि मूढ़ीवादी लोग अपने पैसे को, करार करके फार्मर्स के साथ लगाएंगे और धीरे-धीरे बड़े-बड़े अमीर, जो अमेरिका में हैं, जिनका दो हजार, तीन हजार, चार हजार एकड़ का एक-एक खेत हो, तो ये दो क्षेत्र, जो आज केपिटलिज्म की नागचूढ़ में नहीं हैं, वही क्षेत्र हिन्दुस्तान में केपिटलिस्टों की पॉकेट में आ जाएंगे - ऐसी स्थिति देश में होने की संभावना है। अगर ऐसी स्थिति देश में हो गयी तो देश में democracy नहीं टिक सकेगी। डेमोक्रेसी इसीलिए टिकी है कि हमारे देश में मध्यम वर्ग है और हमारे देश में लाखों की संख्या में small farmers हैं।

Small farmers, marginal farmers ही डेमोक्रेसी की रीढ़ हैं, They are independent. वे इंडीपेंडेंट हैं, इसलिए वे वोट डालकर सरकार को बिगाड़ सकते हैं। इंदिरा जी के शासन में एक बार उन्होंने बता दिया था कि इस देश के जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वे कैसे हैं? एग्रीकल्चर का दूसरा महत्व यह है कि अर्बन डेवलपमेंट के बारे में हम करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए हम तैयार होते हैं, मगर क्यों? देहात टूटकर शहर में क्यों जाते हैं? क्या हम ऐसी कोई रचना नहीं विचार सकते कि देहात का आदमी देहात न छोड़े और शहर में न जाए और देहात टिक सके। आर्थिक दृष्टि से देहात को ऐसा हम क्यों नही बना सकते हैं? वह बनाना है, तो एग्रीकल्चर और जो पशुधन है, आज क्या होता है कि मैं एक छोटा सा ट्रेडर हूं, तो मैं भी गाय रखता हूं, मगर पशुधन का खुद ही बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर से अलग क्यों नहीं हो सकता है? दूध के लिए ही नहीं, पशुधन कोई बोझ नहीं है हिंदुस्तान पर। अपने देश में पशुधन के बारे में संशोधन हुए हैं और संशोधन ऐसे हुए हैं कि जो गाय और भैंस बिलकुल दूध नहीं देती है, ऐसी गाय और भैंस के गोबर की कीमत ही इतनी होती है कि उसमें से उनका खर्चा निकल जाता है और प्रॉफिट होता है। नागपुर के पास एक छोटा सा विलेज है, उसमें उन पर प्रयोग हुआ है और वे गारंटी से कहते हैं कि पशुधन के गोबर की उतनी ही कीमत अच्छी मिल सकती है, ऐसी संभावना है। तो मुझे लगता है कि अपने जो विचार का पहिया है, उसमें थोड़ा डिफेक्ट है, उनको और जोर से, अलग से विचार करना होगा।

महोदय, पानी के बारे में भी मैं कहूंगा। ग्राम का पानी ग्राम में रहे, शहर का शहर में रहे, ऐसी कोई व्यवस्था हो, तो ये बड़े-बड़े डैम बनाने की नीति की जरूरत नहीं पड़ती, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet at 11.00 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at seven minutes pastseven of the clock till eleven of the clock on Friday, 10th of March, 2006

MGIPMRND—187RS—07-07-2006.